Conference of ASIA Energy Vision 2020

2195. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the deliberations of the "Asia energy Vision 2020" conference held in mid-November, 1996 in New Delhi;

(b) if so, what observations and suggestions were made about the foreign investment prospects in power sector and the ways for streamlining the clearance of power projects; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) At the end of "Asia Energy Vision 2020" Conference held in Delhi in mid November, 1996, New Delhi Declaration 96 was issued. According to it, both adequate returns to foreign and domestic investors and avoidance of undue procedural obstacles and institutional barriers are required, to create the conditions which makes investment attractive. Further, in order to attract the investment and its financing, necessary infrastructure has to be strengthened.

The Government, while revising the Power Policy from time to time, takes into account all such suggestions made by various agencies.

मध्य प्रदेश को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराया जाना

2196. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता की धनराशि में कोई कटौती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि की कटौती की गई और उन विशिष्ट योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके संदर्भ में उक्त कटौती की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विविध घटकों के अंतर्गत राज्य योजना क्षेत्रक परिव्यय एवं व्यय विवरण में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के लिए केन्द्रीय सहायता पिछले वर्ष 665.90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 823.33 करोड़ रुपये कर दी गई है। इस प्रकार 1996-97 में मध्य प्रदेश राज्य हेतु केन्द्रीय सहायता में कोई कटौती नहीं हुई है।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 की अवधि के दौरान राज्य योजना क्षेत्रक में एम एन पी घटक के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपये)

क्र० सं०	एमएनपी स्कीम	अनुमोदित परिव्यय	संशो० परि०	वास्तविक परिव्यय	अनु० परि०	संशो०परि०	प्रत्याशित परि०	अनु० परि०	संशोधित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	प्राथमिक शिक्षा	10902.00	7242.81	7878.34	10165.00	8508.63	8847.69	10028.00	8678.00**
2.	व्यस्क शिक्षा	600.00	480.48	456.00	680.00	530.00	530.40	583.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य	2808.00	2262.18	2277.78	3350.00	3921.13	2403.48	2919.00	2919.00
4.	ग्रामीण जलापूर्ति	3950.00	5150.00	4429.00	4968.00	5342.00	5342.00	5656.00	5656.00***
5.	ग्रामीण सड़कें	3000.00	1515.87	546.00	2500.00	1352.30	1352.00	2300.00	1850.00
6.	ग्रामीण आवास	800.00	800.00	546.16	800.00	800.00	800.00	1500.00	1045.00
7.	ग्रामीण विद्युतीकरण	1900.00	1900.00	1936.00	1900.00	1900.00	1900.00	2700.00	2700.00
8.	शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	510.00	530.00	378.00	582.00	591.39	591.39	598.00	598.00
9.	पोषाहार	2000.00	2120.00	1528.00	3000.00	2190.00	2190.00	2200.00	2200.00
10.	ग्रामीण घरेलू रसोई ऊर्जा								
	(1) उन्नत चूल्हे								
	(2) क्षेत्र उन्मुख लकड़ी		244.48			334.00	273.73		
	ईंधन और चारा परियोजना (प्रो०)	150.00			250.00			300.00	10.00
11.	ग्रामीण सफाई	250.00	250.00	134.00	232.00	530.79	531.00	370.00	
12.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	320.00	300.00	0.00	310.00	310.00	310.00	340.00	340.00
	कुल	27190.00	22795.82	20109.28	28737.00	26310.24	25071.69	29494.00	25996.00

* संशोधित परिव्यय को प्रत्याशित व्यय के रूप में समझा जा सकता है।

** इसके अंतर्गत वयस्क शिक्षा का परिव्यय भी शामिल है।

*** इसके अंतर्गत ग्रामीण सफाई का परिव्यय भी शामिल है।

Assistance by IFIs for Power Projects

2208. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some international financial institutions have been extending financial asistance for executive some power projects in the country;

(b) if so, the names of those power projects and of the Financial Institutions funding them; and

(c) the details of funds obtained by those power projects and the progress made by them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) The details of assistance by multilateral funding agencies, i.e., the World Bank and Asian Development Bank for power projects are given in statement I & II respectively.

Double Standards in the Approval of New Refineries

2197. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Minister of Petroleum and Natural Gas has been accused by the private sector of adopting double standards in approving proposals for new refineries;

(b) if so, whether the Ministry has rejected the private sector's proposals for new refineries and have instead given approval to public Undertakings for refineries in Bhatinda and Rai Bareli; and

(c) if so, the reasons for not allowing private sector to participate in the new refineries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS (SHRI T.R. BALLU): (a) to (c) Proposals for